संक्षेप में

पश्चिम बंगाल की 2 फर्मों के लाइसेंस रद्द

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पश्चिम बंगाल की कैलाश फॉर्मुलेशन और सैनेक्योर वाटर प्रोजेक्ट नामक दो कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। नियामक ने कहा, 'दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में चलाए गए प्रवर्तन अभियान में स्वच्छता, साफ-सफाई और अनुपालन संबंधी गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद कैलाश फॉर्मुलेशन और सैनेक्योर वाटर प्रोजेक्ट के एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।' *भाषा*

शैले होटल्स का 5,500 कमरों का लक्ष्य

अतिथि-सत्कार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी शैले होटल्स लिमिटेड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने कमरों की संख्या बढ़ाकर लगभग 5,500 करने का है। शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी श्वेतांक सिंह ने बताया कि कंपनी अपने पारंपरिक परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल से आगे बढ़कर यह विस्तार कर रही है। यह विस्तार शैले के व्यावसायिक मॉडल में आए बदलाव को दर्शाता है। कंपनी अब तीसरे पक्ष द्वारा संचालित होटल, फ्रैंचाइजी संपत्तियों और अपने खुद के 'अथिवा' ब्रांड के तहत होटल को जोड़कर इस लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। कंपनी की आगामी परियोजनाओं के तहत 1,200 से 1,300 कमरे अथिवा ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। सिंह ने कहा, 'अब हम केवल परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तीनों मॉडल पर एक साथ काम कर रहे हैं।' *भाषा*

डीपी आभूषण : 15,000 करोड़ राजस्व की आस

आभूषण खुदरा विक्रेता कंपनी डीपी आभूषण ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी इस अवधि में खासकर दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में अपने स्टोर की संख्या बढ़ाकर 51 करने की योजना बना रही है। डीपी आभूषण के प्रवर्तक विकास कटारिया ने बताया कि कंपनी के फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 स्टोर हैं। *भाषा*

नोब्रोकर का जल्द मुनाफे में आने का लक्ष्य

रियल एस्टेट क्षेत्र के मंच नोब्रोकर.कॉम का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है और कंपनी अगले आठ से 10 महीने में मुनाफे में आने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु स्थित यूनिकॉर्न नोब्रोकर.कॉम की स्थापना 2013 में हुई थी। यह मुख्य रूप से किराये, खरीद और बिक्री के लिए संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराता है और ग्राहकों से कोई ब्रोकरेज शुल्क नहीं लेता है। *भाषा*

मारुति: प्रीमियम हैचबैक पर दांव

चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में इस श्रेणी ने समूचे उद्योग की तुलना में तेज इजाफा दर्ज किया

अंजलि सिंह
मुंबई, 6 सितंबर

मारुति सुजूकी इंडिया प्रीमियम हैचबैक की अहमियत बरकरार रहने पर दांव लगा रही है। हालांकि यात्री वाहन बाजार में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) का दबदबा बढ़ रहा है। यह ऐसे समय हो रहा है, जब चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने के दौरान प्रीमियम हैचबैक श्रेणी ने समूचे उद्योग की तुलना में तेज इजाफा दर्ज किया है।

मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) पार्थो बनर्जी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि फिलहाल प्रीमियम हैचबैक उद्योग का स्तर हर महीने लगभग 50,000 वाहन होने का अनुमान है और इस श्रेणी में मारुति सुजूकी की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है।

बनर्जी ने कहा कि मारुति की प्रीमियम हैचबैक बिक्री अप्रैल और अगस्त के बीच 28 प्रतिशत बढ़ी, जबकि उद्योग की वृद्धि 17 प्रतिशत रही। कंपनी नई बलेनो के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाह रही है। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) समेत कई नई खूबियां हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक देश में यात्री वाहनों का समूचा बाजार 61 लाख से 63 लाख वाहनों तक पहुंच जाएगा। अनुमान है कि तब तक बाजार में एसयूवी की हिस्सेदारी 62 से 63 प्रतिशत होगी, जबकि हैचबैक और मल्टी-पर्पज व्हीकल (एमपीवी) के लिए लगभग 37 से 38 प्रतिशत हिस्सेदारी ही बचेगी।

बनर्जी ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह उद्योग लगभग 63 लाख वाहनों का होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि मारुति को गैर-एसयूवी श्रेणी में काफी गुंजाइश दिख रही है। कंपनी का अनुमान है कि साल 2030 तक यह बाजार लगभग 25 लाख वाहनों तक पहुंच सकता है, जबकि इस क्षेत्र में उसका अपना कारोबार मौजूदा लगभग 6 लाख वाहनों से दोगुना बढ़कर 12 लाख वाहनों तक हो सकता है।

फिलहाल मारुति हर महीने लगभग 16,000 से 16,500 बलेनो बेचती है। उसकी फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर की लगभग 17,000 से 18,000 गाड़ियां बिकती हैं। दोनों मॉडल एक ही प्रोडक्शन लाइन पर बनाए जाते हैं। साथ ही कंपनी दोनों मॉडलों की प्रतीक्षा अवधि के आधार पर इनका उत्पादन घटाती-बढ़ाती है। कंपनी ने इस सप्ताहांत लगभग 6.1 लाख रुपये से शुरू होने वाली नई बलेनो बाजार में उतारेगी।

नई बलेनो में एडीएएस के साथ ह्यूमन डिटेक्शन की सुविधा भी मिलेगी। बनर्जी के अनुसार प्रीमियम हैचबैक श्रेणी में ऐसा पहली बार हो रहा है। कंपनी इन नई खूबियों को उन महानगरीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश कर रही है, जिनतो ऐसे मॉडलों की तलाश होती है जो उनकी जीवनशैली और व्यक्तित्व से मेल खाते हों।

अब बलेनो के ग्राहकों में से लगभग 46 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो पहली बार कार खरीद रहे होते हैं। साथ ही मारुति को कंपनियों और स्टार्टअप मालिकों की ओर से भी बढ़ती दिलचस्पी देखने को मिल रही है। मारुति ने नई बलेनो की बुकिंग 11,000 रुपये में शुरू कर दी है।

पार्थो बनर्जी
वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री)
मारुति सुजूकी इंडिया

बढ़ेगी बाजार हिस्सेदारी

- प्रीमियम हैचबैक उद्योग की दर अनुमानित रूप से लगभग 50,000 वाहन प्रति माह है और इस श्रेणी में मारुति की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है
- मारुति की प्रीमियम हैचबैक बिक्री अप्रैल और अगस्त के बीच 28 प्रतिशत बढ़ी, जबकि उद्योग की वृद्धि 17 प्रतिशत रही
- नई बलेनो के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाह रही है कंपनी, जिसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम समेत शामिल हैं कई खूबियां
- कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक देश में यात्री वाहनों का समूचा बाजार 61 लाख से 63 लाख वाहनों तक पहुंच जाएगा
- अनुमान है कि तब तक एसयूवी की बाजार हिस्सेदारी 62 से 63% होगी, हैचबैक व मल्टी पर्पज व्हीकल के लिए 37 से 38% ही बचेगी हिस्सेदारी

डीमर्जर के बाद की तैयारी

एचईजी करेगी 5,500 करोड़ का पूंजीगत खर्च

सोहिनी दास
मुंबई, 6 सितंबर

एचईजी एडवांस्ड मैटेरियल्स डीमर्जर के बाद अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना बना रही है। इसमें सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मैटेरियल्स को वृद्धि के लिए सबसे अहम माना जा रहा है।

कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी मांग को पूरा करने पर ध्यान दे रही है। एचईजी की योजना है कि वह वित्त वर्ष 2032 तक एनोड मैटेरियल की क्षमता को शुरुआती 20,000 टन से बढ़ाकर 60,000 टन करे। साथ ही, वह अपने बैटरी एनर्जी सॉल्युशंस और ग्रीन-पावर बिजनेस का भी विस्तार करेगी। योजनाबद्ध निवेश में एनोड बिजनेस का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा।

एनोड मैटेरियल की क्षमता 60,000 टन करने की योजना बना रही कंपनी

बिज़नेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कंपनी के चेयरमैन, एमडी और सीईओ ऋजु झुनझुनवाला ने कहा, 'इस डीमर्जर का मकसद वैल्यू हासिल करना, निवेशकों को हर बिजनेस लाइन तक केंद्रित पहुंच देना और शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाना है।' उन्होंने कहा, 'इससे अलग हुई कंपनियों को बेहतर फंडिंग स्वायत्तता और एक खास व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा भी मिलेगी।' एचईजी लगभग 5,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये (इक्विटी के जरिये) और 4,000 करोड़ रुपये कर्ज से जुटाने की योजना बना रही है, जो 27:73 का अनुपात होगा। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक स्थिर रिटर्न हासिल करना है। इसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल लगभग 17 प्रतिशत होगा।

सबसे पहले एनोड बिजनेस को वाणिज्यिक स्तर पर लाने पर ध्यान दिया जाएगा। 20,000 टन क्षमता वाले पहले चरण का काम चल रहा है और वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। इंजीनियरिंग का काम पूरा हो चुका है और खरीद का 85 फीसदी काम भी हो गया है। साथ ही, बाद में इस संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 30,000 टन किया जा सकता है। कंपनी पिछले 12 महीनों से मध्य प्रदेश के मंडीदीप में 200 टन का डेमोंस्ट्रेशन प्लांट का भी संचालन कर रही है।

विस्तार से मणिपाल होगी और दमदार

सोहिनी दास
मुंबई, 6 सितंबर

मणिपाल हॉस्पिटल्स अपनी विस्तार योजनाओं के तहत 2,426 बेड में से लगभग 80 प्रतिशत बेड ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (नए सिरे से निर्माण) के जरिय निर्मित करने की योजना बना रही है। इससे संकेत मिलता है कि कई वर्षों तक अधिग्रहण के जरिये वृद्धि करने के बाद अब कंपनी नए सिरे से अस्पताल बनाने पर भरोसा कर रही है।

यह अस्पताल श्रृंखला साल 2030 तक नए विस्तार के जरिये लगभग 1,943 बेड और पहले से मौजूद अस्पतालों के विस्तार के जरिये 483 बेड जोड़ने की योजना बना रही है। 5 अगस्त को शेयर बाजार पर सूचीबद्धता के बाद कंपनी की पहली सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इस तरह नए सिरे से विस्तार योजनाओं में बेड की हिस्सेदारी कुल नियोजित क्षमता का 80.1 प्रतिशत है।

इस विस्तार में मुख्य रूप से उन बाजारों पर ध्यान दिया जाएगा जहां मणिपाल की पहले से मौजूदगी है। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वी भारत शामिल है। कंपनी इन बाजारों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर,, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अधिग्रहण पर विचार कर रही है। उसने मुंबई-पुणे कॉरिडोर की विकास के मौके के तौर पर पहचान की है। वह दिल्ली-एनसीआर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अधिग्रहण पर भी विचार कर रही है।

अलबत्ता ग्रीनफील्ड विस्तार के लिए शुरुआत में ही काफी निवेश की जरूरत होती है। मणिपाल हॉस्पिटल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी दिलीप जोस ने पहले हुई बातचीत के दौरान बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया था कि लगभग 250 बेड वाले नए अस्पताल के लिए आम तौर पर जमीन और इमारत निर्माण लागत को छोड़ दें तो 380 करोड़ रुपये से 390 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा था कि चिकित्सा उपकरण, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आंतरिक साज-सज्जा पर होने वाला खर्च प्रति बेड लगभग 1.5 करोड़ रुपये बैठता है। इस हिसाब से जमीन और इमारत निर्माण की लागत को छोड़कर नए सिरे से तैयार किए जाने वाले नियोजित 1,943 बेड के लिए लगभग 2,915 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ सकता है। यह प्रति बेड निवेश के आधार पर किया गया अनुमानित हिसाब है। मणिपाल के मौजूदा अस्पतालों में भी विस्तार की गुंजाइश है। वित्त वर्ष 2026 में इसकी मरीज दर 64.5 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह 67.1 प्रतिशत थी। लेकिन इस दौरान ऑपरेशनल बेड की संख्या 5,179 की तुलना में 20.2 प्रतिशत बढ़कर 6,227 हो गई। आम तौर पर कंपनी तब अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने पर विचार शुरू कर देती है, जब किसी अस्पताल में बिस्तर पर मरीज दर 70 प्रतिशत के करीब पहुंच जाती है, ताकि मौजूदा अस्पतालों पर दबाव बढ़ने से पहले ही निर्माण कार्य के लिए समय मिल सके। यह विस्तार योजना विलय-अधिग्रहण से हुई तेज वृद्धि के बाद सामने आई है।

आरपीजी लाइफ की नजर बड़ी एपीआई परिसंपत्तियों पर

सोहिनी दास
मुंबई, 6 सितंबर

आरपीजी लाइफ साइंसेज पांच सप्ताहों में दो अधिग्रहणों पर लगभग 215 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब बड़ी ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (एपीआई) परिसंपत्तियों की तलाश कर रही है। यह दवा कंपनी अपने एपीआई व्यवसाय को तेजी से बढ़ाना और विदेशी बाजारों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना चाहती है।

प्रबंध निदेशक अशोक नायर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमारे पास 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी है और हम अपने एपीआई व्यवसाय को मजबूत करने के मौकों पर तेजी से विचार कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि कंपनी खास तौर पर ऐसे व्यवसाय पर विचार कर रही है जो अलग तरह की केमिस्ट्री, नियामकीय पहुंच और अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) से मंजूर क्षमताएं जोड़ सकें।

नायर ने कहा कि आगे होने वाले सौदों का समय पहले से तय

अशोक नायर
प्रबंध निदेशक, आरपीजी लाइफ साइंसेज

अधिग्रहण की संख्या के बजाय रणनीतिक तालमेल, मूल्यांकन, समेकन की तैयारी और रिटर्न पर निर्भर करेगा।

आरपीजी लाइफ साइंसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई आरपीजी ऐक्टिव फार्मा (आरपीजीएपी) ने पिछले सप्ताह राघव लाइफ साइंसेज के एपीआई और इंटरमीडिएट्स बिजनेस को लगभग 135 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया। इससे पहले 29 जुलाई को उसने लगभग 80 करोड़ रुपये में एक्टिस जेनेरिक्स का अधिग्रहण किया था, जिससे सौदों की कुल कीमत लगभग 215 करोड़ रुपये हो गई। आरपीजी ने राघव के साथ हुई इस डील को एक बड़े और समेकित एपीआई बिजनेस बनाने की 'बाय-ऐंड-बिल्ड' रणनीति का हिस्सा बताया है।

इन दो सौदों ने व्यवसाय की दिशा बदली है। नायर के अनुसार आरपीजीएपी की निर्माण क्षमता 110 किलोलीटर (केएल) से बढ़कर 505 केएल हो गई है। उसके उत्पाद पोर्टफोलियो में 14 से 45 उत्पाद शामिल हो गए हैं और ग्राहक आधार 123 से बढ़कर 250 से ज्यादा हो गया है। कर्मचारियों की संख्या 217 से बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई है, जबकि उसके शोध एवं विकास संबंधित ऑर्डर प्रवाह में शामिल उत्पादों की संख्या 12 से बढ़कर 28 हो गई है।

यह विस्तार ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया भर की दवा कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना चाहती हैं।

बीटा ड्रग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नंदपुर, लोधीमाजरा रोड, बद्दी, जिला सोलन, एच.पी. 174101
टेलीफोन : 01795-236169, ईमेल: cs@betadrugslimited.com
वेबसाइट : www.betadrugslimited.com, सीआईएन : L24230HP2005PLC028969

21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को पूर्वा. 10:30 बजे कंपनी के ग्राम नंदपुर, लोधीमाजरा रोड, बद्दी, जिला सोलन, एच.पी. 174101 में स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी, जिसमें एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा।

बैठक में शामिल होने और वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर शामिल होने और वोट देने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त कर सकता है और परोक्षी कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रभावी होने के लिए, परोक्षी प्रपत्र समुचित रूप से भरकर और हस्ताक्षर करके, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, एजीएम आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा करना होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 समय–समय पर संशोधित के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के प्रावधान के अनुपालन में

1. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।
2. रिमोट ई–वोटिंग 26 सितंबर, 2026 (पूर्वा. 9:00 बजे) आरंभ होगी और 29 सितंबर, 2026 (अप. 5:00 बजे) समाप्त होगी।
3. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 से बुधवार, 30 सितंबर, 2026 तक बंद रहेंगी। (दोनों दिन सहित)।
4. रिमोट ई–वोटिंग से वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ डेट 23 सितंबर, 2026 है।
5. कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषण के पश्चात कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ डेट अर्थात 23 सितंबर, 2026 तक शेयर धारक है, वह evoting@nsdl.co.in/helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
6. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि:–
   ए) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को इंस्टावोट द्वारा 29 सितंबर, 2026 को अप. 5:00 बजे के पश्चात अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   बी) एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट नहीं दिया है, वे आगामी बैठक में मत पत्र से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   सी) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
   डी) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ डेट तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित किए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और मत पत्र से वोटिंग की सुविधा का उपयोग कर सकेगा।
   ई) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.betadrugslimited.com और स्टॉक एक्सचेंज नामतः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
   एफ) किसी प्रश्न के लिए सदस्यगण cs@betadrugslimited.com पर ईमेल लिख सकते हैं अथवा सुश्री रजनी बराड़, कंपनी सचिव, बीटा ड्रग्स लिमिटेड, एससीओ–184, सेक्टर–5, पंचकूला–134114 से फोन 0172–2585483 पर संपर्क कर सकते हैं।

बीटा ड्रग्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
रजनी बराड़
एसीएस24684
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 07–09–2026
स्थान : बद्दी

Capital Small Finance Bank

Capital Small Finance Bank Limited
H.O: MIDAS Corporate Park, 3rd Floor, 37 G.T. Road, Jalandhar City

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक सूचना दिनांकित **20–08–2026** निम्नलिखित कर्जदारों एवं गारंटरों को भेजी गई थी, जो डाक विभाग द्वारा बिना वितरित किए वापस आ गया और प्राधिकृत अधिकारी का सुविवेचित आधार पर मानना है कि कर्जदार/गारंटर सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं, अतएव उन्हें इस बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

कर्ज़दार(रों) और गारंटर(रों) का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	स्वीकृत सुविधा का प्रकार/ऋण संख्या स्वीकृत एवं बकाया राशि
कर्जदार : मैसर्स श्री बाला जी केमिकल्स, 12, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, सिरसा रोड, फतेहाबाद– 125050 में स्थित, इसके स्वामी **श्री महेंद्र सिंह के माध्यम से प्रेषिती क्रमांक: 1** (डब्ल्यूसीटीएल में कर्जदार), श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशन निवासी अयालकी, अयालकी (129), फतेहाबाद, हरियाणा–125051. प्रेषिती **क्रमांक: 2 (मैसर्स श्री बाला जी केमिकल्स में स्वामी), श्रीमती कविता रानी पत्नी श्री महेंद्र सिंह** निवासी 17, ब्लॉक नंबर 12, अयालकी, अयालकी (129), फतेहाबाद, हरियाणा–125051. **प्रेषिती क्रमांक: 3 (डब्ल्यूसीटीएल में गारंटर), श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री राम किशन** निवासी 344, **प्रेषिती क्रमांक: 4 (डब्ल्यूसीटीएल में गारंटर)**	**प्राथमिक प्रतिभूति अचल संपत्ति का समतामूलक बंधक:– संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** मौजा फतेहाबाद, तहसील और जिला फतेहाबाद में स्थित संपत्ति परिमाप 3 कनाल 2 मरला श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री राम किशन के नाम पर सेल डीड है, जिसका दस्तावेज नंबर 4788 दिनांकित 02–11–2017 (खसरा नंबर 178//1/2/1 (5–3) शर 62/103 मुंतकिला 3के–2एम)	**डब्ल्यूसीटीएल/146612000038 स्वीकृत राशि : रू. 30,00,000/– बकाया राशि: रू. 30,84,138.86 (01–08–2026 से लागू ब्याज को छोड़कर)**

बैंक, एतद्द्वारा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत इस सार्वजनिक सूचना द्वारा आपसे बैंक की **हिसार शाखा** की लेखा बहियों में आपके नाम समय–समय पर बकाया सभी राशियों का भुगतान करने और इस तरह इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के प्रति अपनी सभी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने की मांग करता है, ऐसा नहीं करने पर बैंक आपके खर्च और जोखिम पर अधिनियम (सुप्रा) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित सभी या कोई भी उपाय करेगा नामतः– (ए) प्रतिभूत आस्ति के नकदीकरण हेतु बिक्री (बी) प्रतिभूत आस्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, जिसमें प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है, जिसमें प्रतिभूत आस्तियों के नकदीकरण और बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है। (सी) प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंधन हतु कोई व्यक्ति नियुक्त करना। (डी) ऐसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय लिखित रूप में मांग करना, जिसने बैंक को भुगतान करने के लिए आपसे कोई भी प्रतिभूत आस्ति अधिग्रहीत की है। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि यदि कर्जदार/गारंटर यह सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर अपनी देयता पूरी तरह से चुकाने में असफल हो जाता है और बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप–धारा 4 के तहत कोई कार्यवाही करता है, तो कर्जदार/गारंटर को बैंक को उस संबंध में हुए सभी लागत, शुल्क और खर्चे देने होंगे। यदि प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री से बैंक की बकाया राशि पूरी तरह नहीं चुकाई जाती है, तो बैंक आपसे और गारंटर से और इसके लिए जिम्मेदार दूसरे लोगों से बाकी राशि वसूल करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। यह सूचना बैंक के बाकी सभी अधिकारों, उपायों और बैंक को उपलब्ध कानूनी सहायता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के जारी की गई है।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी

अशोक सूटा : एक उद्यमी, काम के धुनी

अभीक दास
बेंगलूरु, 6 सितंबर

एक के बाद एक नया कारोबार स्थापित करने वाले ज्यादातर उद्यमी जब 83 साल की उम्र में आराम करना, सक्रिय कार्यों से हटना और अपनी जिंदगी भर की मेहनत के फल का आनंद लेना पसंद करते हैं, ऐसे समय में भी अशोक सूटा अलग ही राह चुन रहे हैं। स्वास्थ्य और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रति जुनूनी 80 से ज्यादा उम्र वाले अशोक सूटा ने हाल में अपनी दूसरी कंपनी हैपिएस्ट माइंड्स में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी आईटीसी इन्फोटेक को बेचने का ऐलान किया है।

सूटा हैपिएस्ट माइंड्स के नियंत्रक प्रवर्तक का पद छोड़ रहे हैं और उस कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हैं जिसे उन्होंने साल 2011 में स्थापित किया और साल 2020 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया था। कंपनी 110 प्रतिशत के प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुई थी।

लगातार नए उद्यम स्थापित करने वाले सूटा अब अपनी डायग्नोस्टिक हेल्थकेयर और वेलनेस कंपनी हैपिएस्ट हेल्थ और बिना लाभ वाले चिकित्सा अनुसंधान ट्रस्ट स्कैन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

सूटा हैपिएस्ट माइंड्स में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी आईटीसी इन्फोटेक को बेचकर मिलने वाले पैसे से अपने दो उद्यमों का विस्तार करना चाहते हैं। इन्हें साल 2021 और 2022 के बीच शुरू किया गया था। इस सौदे के तहत उनकी लगभग 22.1 प्रतिशत हिस्सेदारी दो चरणों में 1,300 करोड़ रुपये नकद में आईटीसी की सहायक कंपनी को हस्तांतरित की जा रही है। विलय के बाद बनने वाली कंपनी में 7.55 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वह अल्पांश शेयरधारक बन जाएंगे।

यह तुरंत नहीं पता चल सका कि इस कमाई का कितना हिस्सा इन दो उद्यमों को जाएगा। मंगलवार को हुए संवाददाता सम्मेलन में वह शामिल नहीं थे। पहले उन्होंने स्कैन के लिए 200 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई थी। स्कैन आईआईएससी के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और बेंगलूरु के सेंट जॉन्स जेरियाट्रिक सेंटर के साथ मिलकर उम्र बढ़ने और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों पर चिकित्सा अनुसंधान करती है।

हैपिएस्ट माइंड्स के प्रबंध निदेशक वेंकटरमन नारायणन ने कहा, 'सूटा अपने नए उद्यम के लिए रकम जुटाने के लिए हैपिएस्ट माइंड्स में अपना निवेश कम करने पर विचार कर रहे थे।' उन्होंने कहा, वह यह विरासत छोड़ना चाह रहे हैं। यह रकम शेयर बेचकर आएगी। उन्होंने कुछ बड़े सौदों के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी। लेकिन बड़ा सौदा करने के अपने नकारात्मक पहलू होते हैं, जो शेयर की कीमत और शेयरधारकों के मनोबल को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक रणनीतिक निवेशक के साथ कोई छोटा सौदा करने की योजना थी।'

स्कैन ने हाल में बेंगलूरु के अत्तिबेले में 22,000 वर्ग फुट का परिसर खोला है। इस पहल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्वाड्रम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेज और वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट भी साझेदार है।

चंडीगढ़ संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा सी/ओ आइडिया को वर्किंग, तृतीय तल, एस.सी.ओ 32, 33, 34 सेक्टर–17–सी, चंडीगढ़–160017 से प्रकाशित एवं तन्मय महेश्वरी, इम्प्रेशंस प्रिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.–22, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, पंचकूला–134115, हरियाणा से मुद्रित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. CHAHIN/2008/24509 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
स्वामित्व : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें – सुश्री मानसी सिंह, हेड–कस्टमर रिलेशन्स। बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पीबी मार्ग, वर्ली, मुंबई–400013 ईमेल : subs_bs@bsmail.in या 57575 पर REACHBS एसएमएस करें। कोई हवाई अधिभार नहीं